सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. अजीत केतकर

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 4/2023

दिनांक : 01/05/2023

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

विषय : मई दिवस अमर रहे

आप सभी देश-दुनिया के समस्त मेहनतकश वर्ग के साथ ही बीमा कर्मियों को हम मई दिवस के मौके पर क्रांतिकारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

इस बार का मई दिवस अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच आयोजित हो रहा है। ज्ञात हो कि आज से ठीक 137 वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे के काम के अधिकार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों के ऊपर 'गोलियों की बारिश कर तीन मजदूरों की हत्या' कर दी गई थी व मजदूर नेताओं को फांसी दे दी गई थी। इन्हीं शहीदों की याद में प्रत्येक वर्ष ''मई दिवस'' का आयोजन पूरे विश्व में किया जाता है। यह वर्ष भारत में मई दिवस मनाने का शताब्दी वर्ष भी है। 1923 में भारत में मद्रास में सर्वप्रथम मई दिवस मनाया गया था। समूचा विश्व 2008 से जारी वैश्विक महामंदी के बाद एक बार फिर मंदी के दौर से गुजर रहा है। वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक के अनुसार विश्व की आर्थिक वृद्धि 2021 के 6 प्रतिशत से घटकर 2022 में 3.02 प्रतिशत तथा 2023 में 2.7 प्रतिशत होगी। ब्लूमबर्ग ने अक्टूबर 2023 तक अमेरिका में 100 प्रतिशत मंदी की आशंका व्यक्त की है। वैश्विक मुद्रास्फीति की दर 2021 के 4.7 से बढ़कर 2022 में 8.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा प्रायोजित यूक्रेन युद्ध ने इस आग में घी डालने का ही काम किया है। अपने मुनाफे की हवस की पूर्ति के लिए पूंजीपति वर्ग द्वारा मेहनतकशों के खिलाफ वर्गीय हमलों को लगातार तेज किया जा रहा है। इससे सामान्य लोगों के जीवन में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और बदहाली में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि इन नीतियों के खिलाफ वैश्विक प्रतिरोध भी तेज हुआ है। अमेजान के कर्मचारियों ने कई देशों में काम बंद किया है, बावजूद इसके कि निगम ने यूनियनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। फ्रांस में श्रम कानूनों में सुधार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और बढ़े हुए टैक्स के बोझ के खिलाफ 'येलो वेस्ट्स' की जुझारू कार्यवाहियां हुईं। ग्रीस में बड़ी हड़तालें हुईं हैं। यह एक अहम विशेषता है कि कामगार जनता के इन संघर्षों को किसानों, महिलाओं, हरित कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और युवाओं ने सक्रिय समर्थन व सहयोग दिया है। कई देशों में इस तरह की विरोध मुहिम की ताकत ने, प्रगतिशील और गैर दक्षिणपंथी ताकतों का पक्ष लेते हुए चुनावों को प्रभावित किया है। निश्चय ही विश्व मेहनतकशों का यह संघर्ष तीव्र होगा।

आज देश की स्थिति पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हर तरफ, हर वर्ग में चाहे वह मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान, छात्र, नौजवान व गृहिणी जबर्दस्त असंतोष का माहौल है। केंद्र सरकार ने जो सीमित खर्च किए भी है तो उनका भी वित्त पोषण राजकीय परिसंपत्तियों को बेचने के जरिए किया गया है। नये निवेशों का वित्त पोषण मुख्यत: दो तरीकों से हो रहा है - सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी के विनिवेश से और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण या उनकी बिक्री से। राजस्व जुटाने के लिए सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री वास्तव में उन्हें कार्पोरेटों के हवाले करने का बहाना बन गई हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईप लाइन के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए

की जमीन रेलमार्ग, स्टेशन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ईंधन पाईप लाइन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य परिसंपत्तियां बेची जाएंगी और सरकार के पूंजी व्यय के वित्त पोषण के लिए अमीरों पर कराधान से संसाधन जुटाने के बजाए इन्हीं प्राप्तियों का सहारा लिया जा रहा है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी की संपत्ति में भारी गिरावट आई है तथा विश्व के सबसे अमीरों की सूची में वह द्वितीय स्थान से बुरी तरह फिसलकर 38वें स्थान पर जा चुका है। सरकार इसकी जेपीसी जांच कराना तो दूर इस पर अपना मुंह तक खोलने राजी नहीं है और अडानी पर उठ रहे सवाल को देशी पूंजीपति पर हमला करार देकर इसे राष्ट्रवाद की आड़ में छिपाने में लगी है। यह शासक वर्ग की कार्पोरेट परस्ती और दरबारी पूंजीवाद का चरम उदाहरण है।

संयुक्त राष्ट्र की 'वैश्विक खुशी रिपोर्ट' के अनुसार भारतीय अधिक नाखुश हैं। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का स्थान 126 है। अर्थात् 125 देशों के नागरिकों से ज्यादा दुखी भारतीय हैं। भारत अपने पड़ौसी देशों से भी पीछे है। नवउदारवाद की उपज के रूप में बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद अत्यधिक सुखवाद, बढ़ता लालच, छल और धोखाधड़ी, दरबारी पूंजीवाद की चरम लूट का यह खेल, आत्म उन्नति का जुनून लोगों को और अधिक दुखी कर रहा है क्योंकि लोगों को अपने स्वयं के आधिपत्य के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

महंगाई, बेराजगारी चरम पर है। सांप्रदायिक विभाजन के जरिये चुनावी लाभ के लिए वर्तमान में केंद्र में सत्तासीन शक्ति ने ऐसा घृणा का माहौल पैदा कर दिया है जो समाज में उन्माद और हिंसा को प्रोत्साहित कर रहा है। लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके निशाने पर हैं। मेहनतकश वर्ग के द्वारा लंबे संघर्ष से प्राप्त अधिकार भी छीने जा रहे हैं। श्रम कानून को बदलकर श्रम संहिता बना देना और 8 घंटे के काम के अधिकार पर भी हमला कर मालिक की मर्जी पर काम के घंटे निर्धारण की छूट ने श्रमिकों के अमानवीय शोषण का मार्ग प्रशस्त करने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसके खिलाफ देश के मजदूर, किसान, खेत मजदूर और मेहनतकश जनता का संग्राम ही इनका विकल्प है। व्यापक एकताबद्ध यह शक्ति ही निजीकरण, उदारीकरण तथा कार्पोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ की इस लूट के खेल के विरुद्ध जनपक्षीय विकल्प और जनता की पीड़ा से राहत की दिशा तय कर सकती है।

राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग, चाहे वह एलआईसी हो या आम बीमा की सार्वजनिक कंपनियां, इन नीतियों की मार से अछूती नहीं हैं, इसलिए समय अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है और वर्ष 2023 हमें अवसर उपलब्ध करा रहा है कि हम राजनीतिक रूप से ऐसी शक्ति को पराजित करने एवं उसके विकल्प में अपनी महती भूमिका निभाएं क्योंकि इस वर्ष देश के अनेक राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही वर्ष 2024 आम चुनाव का वर्ष होगा जिसमें दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक ताकतों को पराजित करने के अलावा अन्य रास्ता मजदूर वर्ग के पास नहीं है। सही राजनैतिक और वैचारिक समझ के बिना इसका मुकाबला संभव नहीं है। वर्तमान सरकार नवउदारवाद की नीतियों को लागू करने जिस तीव्रता के साथ हमले कर रही है उसी अनुसार सशक्त और संयुक्त प्रतिरोधी कदमों से ही इसे पीछे धकेला जा सकता है। आज संगठित हों या असंगठित क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र सरकारी हमले की जद में हैं तथा वह न्यूनतम वेतन सहित सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को लागू कराने संघर्षरत हैं। मई दिवस के महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम विश्व के मेहनतकशों के साथ एकजुटता का इजहार कर एक बेहतर कल के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे और बीमाकर्मी, मजदूर वर्ग के हिस्से के तौर पर इसमें अवश्यंभावी रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

इन्हीं विश्वास के साथ पुनः आप सभी को मई दिवस की क्रांतिकारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव